PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rashtriya Sahara, Delhi
Thursday 25th December 2014, Page: 15
Width: 15.99 cms, Height: 12.95 cms, a4, Ref: pmin.2014-12-25.47.98

आने वाले वर्ष में जीवनरक्षक दवाएं होंगी सस्ती

ज्ञानेंद्र सिंह/एसएनबी

नई दिल्ली। यह वर्ष दवा उद्योगों के लिए चाहे जैसा रहा हो, मगर 'नया-वर्ष' अंग्रेजी और देशी दवाओं के लिए काफी शुभ होगा। गरीबों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए 'जन-औषधि केंद्रों' का नेटवर्क बढ़ाया जाएगा और उनमें बिकने वाली जेनरिक दवाओं की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। आपात स्थिति में मिलने वाली महंगी जीवन रक्षक दवाओं को भी सस्ता करने का लक्ष्य है। ये सारे फैसले वर्ष के अंतिम समय में लिए गए है।

वर्ष के जाते-जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी के साथ देशी दवाओं के उत्पादन व गुणवत्ता पर भी जोर दिया था जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन मंत्रालय ने एक व्यापक योजना बना ली है जिस पर नए वर्ष से क्रियान्वयन होना शुरू हो जाएगा। जन औषधि केंद्रों में आम आदमी की पहुंच बनाने के लिए इसके केंद्र सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों के निकट खोले जाएंगे। विशेष महत्वपूर्ण बल्क दवाओं व फार्मास्यूटिकल्स सामान के लिए देश की निर्भरता को बढ़ाने के लिए हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल शिक्षा रिसर्च (एनआईपीईआर) में राष्ट्रीय बल्क दवा शोध एवं विकास केंद्र खोलने का प्रस्ताव किया गया है ताकि कम कीमत के साथ बेहतर गुणवत्ता वाली दवा उत्पादन एवं प्रतिस्पर्धा की तकनीक विकसित हो सके। इसके तहत दवा उद्योग क्षेत्र में क्षमता सृजन के नए प्रयासों को और मजबूती प्रदान की जाएगी।

कैशलेस इलाज के कारण दवा एवं चिकित्सा क्षेत्र में घरेलू मांग बढ़ी है और इसे पूरा करने के लिए फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में गुणवत्ता, उत्पादकता व आधुनिकता के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम फार फार्मा सेक्टर (सीडीएस-पीएस) की स्थापना 27 अक्टूबर हो चुकी है। इससे दवा एवं फार्मा के क्षेत्र में विश्व बाजार में भारतीय भूमिका को अग्रणी व सक्षम बनाया जाएगा। इस वर्ष अस्पतालों, सरकारी विभागों व उद्योग प्रतिनिधियों को लेकर टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है जिसके नतीजे आने वाले वर्ष में नजर आएंगे। टास्क फोर्स के माध्यम से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए निजी व सरकारी क्षेत्र को मजबूत बनाया जाएगा जिसमें सरकारी क्षेत्र की दो बीमार फैक्टरियों हिंदुस्तान एंटीबायटिक्स लि. व इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लि. के लिए पुनर्वास योजना बनाई गई है जबकि तीसरी दवा कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. के उत्पादन में बीते वर्ष रिकार्ड वृद्धि (243 फीसद) दर्ज की गई है।

दवाओं पर उत्पाद शुल्क को भी कम करने का प्रस्ताव है। कई मदों में यह दस फीसद से घट कर 2.5 फीसद तक करने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशी दवाओं की गुणवत्ता सुधारने व उनके लिए एक नियंत्रण तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है। उल्लेखनीय है कि एक ही मर्ज की कई-कई ब्रांडों की दवा अलग-अलग दामों पर बेची जाती है। दवा के साथ उपयुक्त होने वाले सामान भी मुंह मांगे दामों में बिक रहे है। इस धंधे पर लगाम कसने के लिए सरकार ने वर्ष के जाते-जाते व्यापक योजना बना ली है जिसके नतीजे नव वर्ष से नजर आने लगेंगे।

वर्ष 2014 का लेखाजोखा

- दवाओं पर उत्पाद शुल्क आधा करेगी नरेंद्र मोदी सरकार
- सरकारी दवा फैक्टरियों का भी किया जाएगा कायाकल्प